भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1039
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

किराए के भवनों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय

†1039. **डॉ. आलोक कुमार सुमनः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बिहार के कई जिलों, विशेषकर गोपालगंज जिले में केन्द्रीय विद्यालय दस वर्षों से अधिक समय से किराए के भवनों में चल रहे हैं;
(ख) सरकार द्वारा गोपालगंज जिले में केन्द्रीय विद्यालय हेतु अब तक कुल कितने किराए का भुगतान किया गया है;
(ग) क्या सरकार को इन विद्यालयों को किराए के भवन से स्वयं के भवन में स्थानांतरित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य में कोई भी केन्द्रीय विद्यालय (केवि) किराए के भवनों में संचालित नहीं है। तथापि, संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्थायी स्कूल भवन का निर्माण होने तक प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी आवास में केन्द्रीय विद्यालयों को कार्यात्मक बनाया गया है। बिहार राज्य में कार्यात्मक 50 केन्द्रीय विद्यालयों में से 16 केन्द्रीय विद्यालय संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी भवनों में कार्यात्मक हैं। इन 16 केन्द्रीय विद्यालयों में से 02 केन्द्रीय विद्यालय निर्माण स्तर पर हैं, 02 केन्द्रीय विद्यालय डीपीआर स्तर पर हैं और केन्द्रीय विद्यालय, गोपालगंज सहित शेष 12 केन्द्रीय विद्यालयों के स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि प्रायोजक प्राधिकारियों ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अपेक्षित सीमा में भूमि उपलब्ध नहीं कराई है।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है जो उपयुक्त भूमि की पहचान करने, प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में अंतरण/पट्टे की औपचारिकताएं पूरी करने, निर्माण एजेंसी द्वारा नक्शे/अनुमान प्रस्तुत करने, निधियों की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदनों आदि पर निर्भर करती है।

*****